श्रीकंठिया रामायया मुनिपल्ली

बनाम

द स्टेट ऑफ बॉम्बे (कनेक्टेड अपील के साथ)

[मुखर्जी, एस. आर. दास और विवियन बोस जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, (1898 का अधिनियम 5), धारा 197-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 (1947 का द्वितीय), धारा 5 (2)-इसके तहत प्रभार और धारा 5 के तहत आरोप। भारतीय दंड संहिता की धारा 409 (1860 का अधिनियम 45-एक दूसरे से अलग-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत दी गई मंजूरी-क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 409-दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 और भारतीय दंड संहिता की धारा 34 का दायरा और निर्माण-क्या व्यक्ति को अपराध के वास्तविक कृत्य में शारीरिक रूप से उपस्थित होना चाहिए।

तीन अभियुक्त-सरकारी कर्मचारियों-पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5 (2) के तहत संयुक्त रूप से दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया था और तीनों पर संयुक्त रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 409 के सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में न्यास भंग करने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद कई वैकल्पिक आरोप लगे जिनमें प्रत्येक पर धारा 409 के तहत व्यक्तिगत रूप से

आपराधिक न्यास भंग करने का अलग-अलग आरोप लगाया गया था। एक और विकल्प के रूप में, तीनों पर धारा 409 के तहत विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के लिए, इन आरोपों पर की गई आपत्ति पर अपराध के लिए मुकदमा, एक-दूसरे को उकसाने के लिए धारा 109 के साथ पठित धारा 409 के तहत संयुक्त रूप से आरोप लगाया गया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 (2) को भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत मुकदमे से अलग किया गया था।

आरोप फिर से तय किए गए। धारा 5 (2) के तहत एक को हटा दिया गया था जबकि अन्य बने रहे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत कार्य करने वाले गवर्नर जनरल ने पहले अभियुक्त (अपीलार्थी सं. ।) धारा 120-ख, 409,109 के तहत अपराधों के लिए सरकार से संबंधित संपत्तियों के संबंध में अन्य दो के साथ आपराधिक न्यास भंग करने की साजिश रचने के लिए और इस प्रकार उस अपराध को करने के लिए उकसाने के लिए और इसे करने के लिए भी। इसी तरह की मंजूरी अन्य दो अभियुक्तों के खिलाफ नहीं दी गई थी और यह केवल प्रथम अभियुक्त तक ही सीमित थी। उसी तारीख को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5 (2) के तहत पहले आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई थी और दूसरे आरोपी के खिलाफ भी ऐसा ही अधिकार दिया गया था। सवाल यह था कि क्या यह मंजूरी है। दूसरे अभियुक्त के खिलाफ धारा

409 के तहत उसके अभियोजन को कवर करने के लिए बढ़ाया जा सकता है और क्या उसका मुकदमा वैध था।

दूसरी ओर, यदि दोनों अधिकारी वास्तव में एक हैं, तो चुनाव स्पष्ट रूप से किया गया है। 1952 के अधिनियम LIX और 1952 के अधिनियम LXVI द्वारा संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5 (2) के तहत मंजूरी एक विशेष प्रक्रिया के साथ विशेष अदालतों में आगे बढ़ने के लिए है ताकि दूसरे अभियुक्त के खिलाफ वर्तमान मुकदमा अक्षम हो।

यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि इस प्रकृति का दोष और जब धारा 197 लागू होती है तो ठीक नहीं किया जा सकता है और जैसा कि उसने किया, मंजूरी आवश्यक थी इसलिए मुकदमे को शुरू से ही दूषित कर दिया गया था। तदनुसार कार्यवाही को रद्द कर दिया गया।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 का इतना संकीर्ण अर्थ लगाया गया है कि इसे इसके लिए कभी भी फिर से लागू नहीं किया जा सकता है। अपराध करना किसी अधिकारी के कर्तव्य का हिस्सा नहीं है और न ही कभी हो सकता है। लेकिन यह एक अधिकारी का कर्तव्य नहीं है जिसकी जांच उसके कार्य के रूप में की जानी चाहिए, क्योंकि एक आधिकारिक कार्य आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन के साथ-साथ उसकी अवहेलना में भी किया जा सकता है। धारा की विषय-वस्तु है और इसकी भाषा को अर्थ दिया जाना चाहिए।

प्रथम अभियुक्त के मामले में धारा 34 के तहत जूरी को आरोप में गलत दिशा दी गई थी। गलत निर्देश का सार सत्र न्यायाधीश के जूरी को दिए गए निर्देश में शामिल था कि भले ही कोई व्यक्ति अपराध के वास्तव में किए जाने के समय उपस्थित न हो और भले ही वह "पर्दे के पीछे" रहता हो, उसे धारा 34 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है बशर्ते कि यह साबित हो कि अपराध सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। यह गलत है क्योंकि इस धारा का सार यह है कि व्यक्ति को अपराध के वास्तविक कृत्य में शारीरिक रूप से उपस्थित होना चाहिए।

गलत दिशा स्पष्ट है और मामले की जड़ तक जाती है क्योंकि जूरी ने धारा 409 के तहत दोषी का निर्णय वापस कर दिया जिसे केवल धारा 34 के साथ पढ़ा जाता है और धारा 409 के तहत नहीं जिसे धारा 109 के साथ पढ़ा जाता है, आई. पी. सी. ने माना कि ऐसे मामलों में जो सार और महत्व के सवाल उठाते हैं, उच्च न्यायालयों को उनके सामने उठाए गए बिंदुओं पर अपने विचारों का कुछ संकेत दिए बिना अस्वीकृति के संक्षिप्त आदेश पारित नहीं करना चाहिए।

मुश्ताक हुसैन बनाम बॉम्बे राज्य ([1953] एस. सी. आर. 809), राज्य बनाम गुरुचरण सिंह (ए. एल. आर. [19521 पंजाब 89), गोकुल चंद द्वारकादास बनाम राजा (ए. एल. आर. [1948] पी. सी. 82), होरी राम सिंह बनाम क्राउन ([1939] एफ. सी. आर. 159), मदन मोहन बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य (ए. एल. आर. [1954] एस. सी. 637), लेफ्टिनेंट हेक्टर थोमा हंटले बनाम राजा-सम्राट ([1944] एफ. सी. आर. 262), और बरेंद्र कुमार घोष बनाम राजा-सम्राट ([1924] एल. आर. 52 आई. ए. 40), 1953 की आपराधिक अपील संख्या 1213 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के 23 नवंबर 1953 के निर्णय और आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील और 1952 के सत्र न्यायालय मामले संख्या 36 के 6 अगस्त 1953 के निर्णय और डिक्री से उत्पन्न आपराधिक अपील संख्या 1121 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के 25 अगस्त 1953 के निर्णय और आदेश से संदर्भित।

1954 की आपराधिक अपील संख्या 89 में अपीलार्थी की ओर से एस. नारायणैया और डॉ. सी. वी. एल. नारायण।

1954 की आपराधिक अपील संख्या 90 में अपीलार्थी के लिए सी. संजीवरो नायडु और आर. गणपति अय्यर।

प्रत्यर्थी की ओर से भारत के महान्यायवादी (जी. एन. जोशी और उनके साथ पोरस ए. मेहता) एम. सी. सीतलवाड़।

22 दिसंबर 1954.

न्यायालय का निर्णय जे. बोस ने दिया था।

ये दोनों अपीलें एक ही मुकदमे से उत्पन्न होती हैं। दो अपीलार्थी, श्रीकंठिया (निचली अदालत में पहला अभियुक्त और 1954 की अपील संख्या 89) और परशुराम (दूसरा अभियुक्त. और 1954 की अपील संख्या 90 में

अपीलार्थी) थेः भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के आसपास केंद्रित कई अलग-अलग आरोपों पर तीसरे आरोपी डॉसन के साथ मुकदमा चलाया गयाः लोक सेवक द्वारा विश्वास का आपराधिक उल्लंघन। मुकदमा जूरी द्वारा चलाया गया और तीनों को धारा 34 के साथ धारा 409 के तहत अपराध का दोषी पाया गया। उन्हें दोषी ठहराया गया और निम्नानुसार सजा सुनाई गईः

अभियुक्त नं. 1. श्रीकंठियाको एक साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना, चार महीने के डिफ़ॉल्ट के साथ 500; अभियुक्त सं. 2. परशुराम को दो साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना,छह महीने के डिफ़ॉल्ट के साथ 500; और अभियुक्त संख्या 3 डॉसन को छह महीने की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना, दो महीने के डिफ़ॉल्ट के साथ 200।

उच्च न्यायालय में दूसरे अभियुक्त की अपील को एक शब्द "खारिज" के साथ संक्षेप में खारिज कर दिया गया था। पहले और तीसरे आरोपी ने अलग-अलग अपील की। उनकी अपील को एक अन्य पीठ द्वारा सुना गया और स्वीकार कर लिया गया, और 23-11-1953 पर एक तर्कपूर्ण निर्णय का पालन किया गया। यह, कम से कम कहने के लिए, इस मामले की परिस्थितियों में, विसंगत था। अपील एक ही मुकदमे से उत्पन्न होती है और एक ही फैसले से होती है और जूरी के लिए एक ही आरोप से संबंधित

होती है, और इसके अलावा वे काफी हद तक एक ही बिंदु उठाते हैं। यह न्यायालय अपील की संक्षिप्त अस्वीकृति के प्रति अपनी अस्वीकृति व्यक्त करने के लिए विवश था जो सार और महत्व के मुद्दों को उठाता है. मुश्ताक हुसैन बनाम बॉम्बे राज्य (1) में टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। वे अवलोकन वर्तमान मामले में और भी अधिक बल के साथ लागू होते हैं।

तीनों आरोपी सरकारी कर्मचारी हैं। हर भौतिक समय पर, पहला अधिकारी पूना के पास देहू रोड पर सैन्य इंजीनियरिंग स्टोर डिपो की कमान संभाल रहा था। वह पूरी तरह से प्रभारी थे।

दूसरा उनके अधीन रसीद और निर्गम नियंत्रण अनुभाग के प्रभारी अधिकारी के रूप में था। तीसरा सीधे सहायक स्टोर अधिकारी के रूप में दूसरे के अधीन काम करता था।

डिपो का रखरखाव केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और यह लगभग 150 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। वहाँ कई लाख रुपये की सरकारी दुकानें रखी जाती हैं। 11-9-1948 लोहे की दुकानों पर लगभग रु। 4, 000 अवैध रूप से डिपो से बाहर निकाले गए और उन्हें इब्राहिम फिदा हुसैन को सौंप दिया गया, जो सरकारी गवाह मोहसिनभाई (पी. डब्ल्यू. 1) का एक एजेंट था। अभियोजन पक्ष के लिए मामला यह है कि तीन आरोपी, जो इन भंडारों के प्रभारी थे और जिन्हें उन्हें विभिन्न क्षमताओं में सौंपा गया था,

ने इन संपत्तियों की सरकार को धोखा देने की साजिश रची और इस साजिश के अनुसरण में उन्होंने उन्हें सरकारी गवाह (पीडब्ल्यू 1) को रुपये की राशि में बेचने की व्यवस्था की। 4, 000। कहा जाता है कि पैसे का भुगतान किया गया था और फिर दुकानों को डी से बाहर कर दिया गया था; बर्तन। कहा जाता है कि यह पैसा तीनों अभियुक्तों की जेब में था और सरकार को जमा नहीं किया गया था।

इन तथ्यों पर कई आरोप लगाए गए थे। पहला सेट 9-7-1953 पर तैयार किया गया था। तीनों अभियुक्तों पर संयुक्त रूप से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5 (2) के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया था और तीनों पर संयुक्त रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में आपराधिक न्यास भंग करने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद कई वैकल्पिक आरोप लगाए गए, जिनमें से प्रत्येक पर अलग-अलग धारा 409 के तहत व्यक्तिगत रूप से आपराधिक न्यास भंग करने का आरोप लगाया गया था। एक और विकल्प के रूप में, तीनों पर संयुक्त रूप से धारा 409, भारतीय दंड संहिता की धारा 109 के साथ पठित धारा 409 के तहत विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के लिए एक-दूसरे को उकसाने के लिए आरोप लगाया गया था। इन आरोपों पर तुरंत आपत्ति जताई गई और जो अब हमारी चिंता का विषय है, उसे निम्नलिखित शब्दों में जोड़ा गयाः

"यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के साथ धारा 5 (2), भ्रष्टाचार अधिनियम, 1947 के तहत मुकदमे से अभियुक्त को अपने बचाव में शर्मिंदा होने की संभावना है क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत आरोप पर विचार करते समय जूरी सदस्यों के दिमाग से शपथ पर दिए गए अभियुक्त व्यक्तियों के साक्ष्य (यदि कोई हो) को मिटाना मुश्किल होगा।

इसलिए प्रार्थना की जाती है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 409 और भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत आरोपों का एक साथ एक मुकदमे में मुकदमा नहीं चलाया जाए। सहायक लोक अभियोजक ने कहा कि उन्हें आरोपों को अलग करने और धारा 5 (2) के तहत एक को दूसरे मुकदमे के लिए छोड़ने पर कोई आपत्ति नहीं है।

"इस प्रकार, यद्यपि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत अपराध के लिए एक संयुक्त मुकदमा और भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध कानूनी और वैध हैं, मुझे लगता है कि, ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों को देखते हुए, यह न्याय के हित में होगा और स्वयं अभियुक्तों के हित में भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत अपराध के लिए मुकदमा अलग किया जाएगा। इसलिए मैं इस हद तक आवेदन स्वीकार करता हूं और आदेश देता हूं कि आरोपों में तदनुसार संशोधन किया जाना चाहिए।

इसे ध्यान में रखते हुए आरोपों को 11-7-1953 पर फिर से फ्रेम किया गया। सार का एकमात्र अंतर यह है कि धारा 5 (2) के तहत आरोप हटा दिया गया था बाकी बचे हुए थे। मामला को फिर से फ्रेम किया गया था.

अब यह देखा जाएगा कि सभी अभियुक्त लोक सेवक हैं और उनका तर्क है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, वे अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने के लिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत मंजूरी आवश्यक थी। जहाँ तक पहले अभियुक्त का संबंध है, मंजूरी है लेकिन दूसरा अभियुक्त तर्क देता है कि उसके मामले में उस वर्तमान मुकदमे को सही ठहराने के लिए कोई नहीं है, इसलिए उसका मुकदमा, दोषसिद्धि और सजा खराब हैं।

इसके बारे में स्थिति इस प्रकार हैः 27·10.1949 पर गवर्नर-जनरल ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत कार्य करते हुए धाराओं के तहत अपराधों के लिए पहले आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। धारा 120-ख, 409,109 आदि के तहत अपराधों के लिए पहले अभियुक्त के अभियोजन को मंजूरी दी, अन्य दो के साथ उन संपत्तियों के संबंध में आपराधिक न्यास भंग करने की साजिश रचने के लिए जिनके साथ यह मामला संबंधित है और इस प्रकार उस अपराध को करने के लिए उकसाने के लिए, और इसे करने के लिए भी। इसी तरह की मंजूरी आसानी

से अन्य दो अभियुक्तों के खिलाफ दी जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं था। इन अपराधों के लिए सजा पहले आरोपी तक सीमित थी।

उसी तारीख को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत पहले आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए भी मंजूरी दी गई थी और दूसरे आरोपी के खिलाफ भी इसी तरह की मंजूरी दी गई थी। सवाल यह है कि क्या दूसरे आरोपी के खिलाफ इस मंजूरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत उसके अभियोजन को कवर करने के लिए बढ़ाया जा सकता है। हमारी राय में, यह नहीं हो सकता है।

मंजूरी के दिन भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (1947 का द्वितीय) लागू था। भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत आपराधिक न्यास भंग को 1947 के अधिनियम की धारा 5 (1) (सी) के तहत "आपराधिक दुराचार" की परिभाषा में शामिल किया गया था। इसलिए, धारा 409 के तहत किसी अपराध पर 1947 के अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा सकता था और सवाल यह उठा कि क्या उस अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए, या क्या इसे सामान्य अदालतों द्वारा भी सामान्य तरीके से चलाया जा सकता है। पंजाब उच्च न्यायालय ने राज्य बनाम गुरुचरण सिंह (1) मामले में निर्णय दिया कि वह ऐसा नहीं कर सकता। इस वजह से 1947 के अधिनियम को 1952 में 1952 के अधिनियम एल. आई. एक्स. द्वारा संशोधित किया गया था और संशोधन अधिनियम की धारा 4 यह

स्पष्ट करती है कि मुकदमा किसी भी कानून के तहत हो सकता है। लेकिन उसी वर्ष आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम XLVI) पारित किया गया था और इस अधिनियम के कारण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत मुकदमे एक विशेष न्यायालय के समक्ष होने चाहिए और एक विशेष प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।

इसलिए, इन विभिन्न अधिनियमों ने जो स्थिति बनाई वह यह थी। सबसे पहले, किसी प्राधिकारी को यह चुनने का विकल्प दिया गया था कि क्या किसी अभियुक्त पर विशेष प्रक्रिया के साथ विशेष न्यायालय में मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उसे धारा 5 (2) के तहत कम सजा दी जानी चाहिए या क्या उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत सामान्य तरीके से मुकदमा चलाया जाना चाहिए जिसमें अधिक सजा का खतरा हो।

फिर सवाल यह है कि किसे चुनना है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत गवर्नर-जनरल उस तारीख को मंजूरी देने वाले प्राधिकारी थे, हालांकि "अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग" शब्द उस समय तक हटा दिए गए थे। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मंजूरी देने वाला प्राधिकारी "केंद्र सरकार" था। अब यह अच्छी तरह से हो सकता है कि सामान्य धारा अधिनियम की धारा 8 (ए) के कारण दोनों का अर्थ एक ही हो, लेकिन

इस समय इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तथ्य यह है कि या तो एक या दो सरकारी अधिकारियों को चुनाव कराने का अधिकार दिया गया था और कर्तव्य के साथ निवेश किया गया था। उन्हें यह कहने का अधिकार था कि क्या लोक सेवक के एक निश्चित वर्ग, जिसने आपराधिक न्यास भंग किया था, उस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत देश की सामान्य अदालतों में सामान्य प्रक्रिया के अनुसार मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उस पर अधिकतम दस साल का जुर्माना और असीमित जुर्माना लगाया जाना चाहिए या उसी अपराध के लिए विशेष अदालत में किसी विशेष प्रक्रिया द्वारा दूसरे नाम से मुकदमा चलाया जाना चाहिए और सात साल से अधिक नहीं और एक असीमित जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए। दलीलों के इस चरण में हमने अपीलार्थियों के विद्वान वकील से पूछा कि क्या वे संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत इस कानून के अधिकारों को चुनौती देने का इरादा रखते हैं, क्योंकि अगर वे ऐसा करते हैं, तो मामले को संविधान पीठ में जाना होगा क्योंकि हम, केवल तीन न्यायाधीश होने के नाते, इसे तय करने की कोई शक्ति नहीं होगी। विद्वान महान्यायवादी ने तुरंत आपत्ति जताई क्योंकि यह मुद्दा किसी भी स्तर पर नहीं उठाया गया था और इस न्यायालय में अपील के आधार पर भी नहीं पाया गया था। अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने जवाब दिया कि वे इस मुद्दे को नहीं लेना चाहते हैं। तदनुसार, हमें इस मामले में इस धारणा पर आगे बढ़ना होगा कि 1952 का संशोधन अधिनियम (1952 का अधिनियम

LIX) वैध है। यह उस स्थिति में परिणाम देता है जिसे हमने ऊपर उल्लिखित किया है।

एक विकल्प है, न केवल न्यायाधिकरण का, बल्कि प्रक्रिया और अधिकतम दंड की सीमा का भी। यदि दो अलग-अलग प्राधिकरणों को चुनने का अधिकार दिया जाता है और न तो वे दूसरे के संरक्षण का अतिक्रमण कर सकते हैं, तो गवर्नर-जनरल ने दूसरे अभियुक्त के खिलाफ वर्तमान अभियोजन को मंजूरी नहीं दी है और किसी अन्य प्राधिकरण के पास ऐसा करने की शक्ति नहीं है। इसलिए, उस स्थिति में, धारा 5 (2) के तहत मुकदमा चलाने के लिए दी गई मंजूरी का उपयोग वर्तमान मुकदमे को कवर करने के लिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा दिया गया है जो इसे देने के लिए सक्षम नहीं है।

दूसरी ओर, यदि दोनों प्राधिकरण वास्तव में एक हैं, तो चुनाव स्पष्ट और स्पष्ट रूप से किया गया है। मंजूरी विशेष अदालतों में विशेष प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने के लिए है और दूसरे आरोपी को उच्च दंड के जोखिम का सामना नहीं करना पड़ता है। उस स्थिति में, दूसरे अभियुक्त के खिलाफ वर्तमान मुकदमा अक्षम है।

यह कि इस तरह का एक दोष घातक है और ठीक नहीं किया जा सकता है, अच्छी तरह से तय किया गया है। गोकुलचंद द्वारकादास बनाम राजा (1) में प्रिवी काउंसिल, होरी राम सिंह बनाम क्राउन (2) में

वरदाचारियार, जे. की टिप्पणियाँ और मदन मोहन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (3) में इस न्यायालय का निर्णय देखें। लेकिन विद्वान महान्यायवादी ने तर्क दिया कि किसी भी मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि, उनके अनुसार, दूसरे अभियुक्त के कहने के बावजूद, किसी भी कल्पना से यह नहीं कहा जा सकता है कि वह अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा था, या कार्य करने का भी इरादा रखता था। तर्क इस प्रकार थाः- यहाँ जिस कार्य की शिकायत की गई है वह न्यास भंग है और इसे पूर्व में उकसाने के कारण उल्लंघन हुआः जैसे ही मोहसिनभाई की लॉरी पर माल लादा गया था। माल के अनधिकृत निष्कासन की अनुमति देना इस अभियुक्त के आधिकारिक कर्तव्यों का कोई हिस्सा नहीं थाः इसलिए, जब उसने अनुमति दी कि उसने अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में न तो कार्य किया, न ही कार्य करने का इरादा किया।

लेफ्टिनेंट हेक्टर थॉमस हंटले बनाम राजा-सम्राट (4) मामले में संघीय न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया गया था, जिसमें न्यायमूर्ति जफरुल्ला खान ने कहा था कि "यह स्थापित किया जाना चाहिए कि जिस अधिनियम की शिकायत की गई थी वह एक आधिकारिक कार्य था" और होरी राम सिंह बनाम द क्राउन (1) ए. एल. आर. (1) ए. एल. आर. 1948 पी. सी. 82 मामले में न्यायमूर्ति वरदाचारियार की टिप्पणियों का संदर्भ दिया गया था। (2) [1939] एफ. सी. आर. 159,184 (3) ए. एल. आर. 1954 एस. सी. 637, 641 (4) [1944] एफ. क्यू. आर. 262,269। (5)

1939 एफ. सी. आर 59; 186; जहां, भारतीय दंड संहिता की धारा 409 से निपटने के लिए, वे कहते हैं-"हालांकि एक लोक सेवक के रूप में अभियुक्त की क्षमता का संदर्भ धारा 409 के तहत आरोप और धारा 477-ए के तहत आरोप दोनों में शामिल है, दोनों मामलों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है, जब कोई शिकायत किए गए कार्य से निपटने के लिए आता है।

दोनों मामलों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है, जब कोई शिकायत किए गए कार्य से निपटने के लिए आता है। पहले में, आधिकारिक क्षमता केवल 'सुपुर्दगी' के संबंध में सामग्री है और आवश्यक रूप से दुरुपयोग या रूपांतरण के बाद के कार्य में प्रवेश नहीं करती है, जिसके बारे में शिकायत की जाती है।यह तर्क जिस बात को नजरअंदाज करता है वह यह है कि उद्धृत अंश में "आवश्यक रूप से" शब्द पर जोर दिया गया है जिसे हमने रेखांकित किया है। पृष्ठ 187 पर एक बाद का अंश इसकी व्याख्या करता हैः

"मैं शुरुआत में यह देखूंगा कि यह प्रश्न काफी हद तक तथ्यों में से एक है, जिसे शिकायत किए गए कार्य और परिचर परिस्थितियों के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए; कठिन और तेज़ परीक्षणों को निर्धारित करने का प्रयास करने की भाषा की व्याख्या करना न तो उपयोगी लगता है और न ही वांछनीय। इसके साथ हम सम्मानपूर्वक सहमत हैं। ऐसे मामले और मामले हैं और प्रत्येक का निर्णय अपने तथ्यों पर किया जाना चाहिए।

अब यह स्पष्ट है कि यदि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 का बहुत संकीर्ण रूप से अर्थ लगाया जाता है तो इसे कभी भी लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि निश्चित रूप से अपराध करना किसी अधिकारी के कर्तव्य का हिस्सा नहीं है और न ही कभी हो सकता है। लेकिन यह कर्तव्य नहीं है कि हम अधिनियम की इतनी जांच करें, क्योंकि एक आधिकारिक कार्य आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन के साथ-साथ इसकी अवहेलना में भी किया जा सकता है। धारा की विषय-वस्तु है और इसकी भाषा को अर्थ दिया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है-"जब किसी लोक सेवक पर अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने के लिए कथित रूप से किए गए किसी भी अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो हमें सबसे पहले अपराध शब्द पर ध्यान केंद्रित करना होगा।अब एक अपराध में शायद ही कभी एक ही कार्य होता है। यह आमतौर पर कई तत्वों से बना होता है और एक नियम के रूप में, ऐसा होने से पहले कृत्यों की एक पूरी श्रृंखला को साबित किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, दूसरे अभियुक्त के खिलाफ आरोप लगाए गए तत्व हैं, पहला, कि एक "सुपुर्दगी" और/या "प्रभुत्व" था; दूसरा, कि सुपुर्दगी और/या प्रभुत्व "एक लोक सेवक के रूप में उसकी क्षमता में था"; तीसरा, कि एक "निपटान" था; और चौथा, कि निपटान "बेईमान" था।

अब यह स्पष्ट है कि यहाँ प्रत्यर्पण और/या अधिराज्य एक आधिकारिक क्षमता में था, और यह समान रूप से स्पष्ट है कि इस मामले

में कोई निपटान, वैध या अन्यथा नहीं हो सकता था, सिवाय एक कार्य द्वारा किया गया या किया जाना अभिप्रेत है एक अधिकारी के जिस कार्य की शिकायत की गई थी, अर्थात् निपटान, किसी अन्य तरीके से नहीं किया जा सकता था। यदि यह निर्दोष था, तो यह एक आधिकारिक कार्य था; यदि बेईमान था, तो यह एक आधिकारिक कार्य का बेईमान करना था, लेकिन किसी भी घटना में यह कार्य आधिकारिक था क्योंकि दूसरा आरोपी एक आधिकारिक कार्य करने के अलावा माल का निपटान नहीं कर सकता था, अर्थात् आधिकारिक रूप से उनके निपटान की अनुमति देना; और यह कि उसने किया। उन्होंने वास्तव में उनकी रिहाई की अनुमति दी और एक आधिकारिक क्षमता में ऐसा करने का इरादा किया, और इस तथ्य के अलावा कि उन्होंने निजी तौर पर काम करने का नाटक नहीं किया, कोई अन्य तरीका नहीं था जिसमें वे ऐसा कर सकते थे। इसलिए, इस कार्य के पीछे जो भी इरादा या उद्देश्य रहा हो, उसका भौतिक हिस्सा अपरिवर्तित रहा, इसलिए यदि यह एक मामले में आधिकारिक था तो यह दूसरे में भी समान रूप से आधिकारिक था, और अंतर केवल उस इरादे में होगा जिसके साथ यह किया गया थाः एक मामले में, यह एक आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किया जाएगा और दूसरे में, इसके कथित निर्वहन में।उसके खिलाफ कथित उकसाने का कार्य उसी आधार पर खड़ा है, क्योंकि उकसाने में उसकी भूमिका एक आधिकारिक कार्य करके माल के निपटान की अनुमति देना था और इस प्रकार किसी अन्य व्यक्ति को बेईमानी से उनका

उपयोग करने के लिए "जानबूझकर पीड़ित" करना थाः भारतीय दंड संहिता की धारा 405। दोनों ही मामलों में, उसके मामले में "अपराध" आधिकारिक अधिनियम को साबित किए बिना अधूरा होगा।

इसलिए हम मानते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 लागू होती है और यह मंजूरी आवश्यक थी, और चूंकि कोई मंजूरी नहीं थी, इसलिए मुकदमा शुरू से ही दूषित है। इसलिए हम दूसरे आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के साथ-साथ उसकी दोषसिद्धि और सजा को भी रद्द करते हैं।

अब हम पहले अभियुक्त की अपील की ओर मुड़ते हैं। उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के साथ धारा 34 के तहत दोषी ठहराया गया है। यहाँ मुख्य बिंदु धारा 34 के बारे में जूरी के आरोप को एक महत्वपूर्ण गलत दिशा देने से संबंधित है। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने इस धारा के दायरे और विषय-वस्तु को गलत समझा और इसलिए जूरी को कानून के बारे में गलत दिशा दी।

आरोप के पैराग्राफ 15 और 16 में इस धारा की विस्तार से व्याख्या की गई थी और हालांकि दिए गए कुछ चित्रण सही हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ गलत है और जिस पर अगर कार्रवाई की जाती है, तो यह न्याय की विफलता का कारण बन सकता है। गलत दिशा-निर्देश के सार में जूरी को उनका निर्देश शामिल है कि भले ही कोई व्यक्ति "अपराध वास्तव में किए जाने पर उपस्थित न हो" और भले ही वह "पर्दे के पीछे" रहे, उन्हें धारा

34 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है बशर्ते कि यह साबित हो कि अपराध सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। यह गलत है, क्योंकि यह धारा का सार है कि व्यक्ति को अपराध के वास्तविक कृत्य में शारीरिक रूप से उपस्थित होना चाहिए। उसे वास्तविक कमरे में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है; उदाहरण के लिए, वह अपने साथियों को खतरे के किसी भी दृष्टिकोण के बारे में चेतावनी देने के लिए तैयार बाहर एक गेट के पास पहरा दे सकता है या उनके भागने की सुविधा के लिए पास की सड़क पर एक कार में इंतजार कर सकता है, लेकिन) उसे घटना स्थल पर शारीरिक रूप से मौजूद होना चाहिए और वास्तव में अपराध के समय किसी न किसी तरह से अपराध में भाग लेना चाहिए। विरोधाभास प्रारंभिक चरणों, समझौते, तैयारी, योजना, जो धारा 109 द्वारा कवर किया गया है, और योजना को लागू करने और निष्पादित करने के चरण के बीच है। धारा 34 बाद वाला से संबंधित है।

यह सच है कि किसी प्रकार की प्रारंभिक योजना होनी चाहिए जो अपराध स्थल पर हो या न हो और जो बहुत पहले हो चुकी हो, लेकिन इसमें वास्तविक भागीदारी के साथ घटना स्थल पर शारीरिक उपस्थिति का तत्व जोड़ा जाना चाहिए, जो निश्चित रूप से एक निष्क्रिय चरित्र का हो सकता है जैसे कि एक दरवाजे के पास खड़ा होना, बशर्ते कि उन सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में सहायता करने के इरादे से किया जाता है

और जब उसके लिए "कार्य" करने का समय आता है तो पूर्व व्यवस्थित योजना में अपनी भूमिका निभाने की तैयारी होती है।

धारा 34 में "किया" शब्द पर जोर दिया गया हैः ". जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है।" यह आवश्यक है कि वे कार्य को वास्तविक रूप से करने में शामिल हों, न कि केवल इसके अपराध की योजना बनाने में। इस धारा को लॉर्ड समनर द्वारा बरेंद्र कुमार घोष बनाम द किंग-एम्परर (1) में विस्तृत रूप से समझाया गया है। पृष्ठ 52 पर, वे बताते हैं कि "कार्रवाई में भागीदारी" धारा 34 की प्रमुख विशेषता है। और भारतीय दंड संहिता की धारा 114 की व्याख्या करते हुए पृष्ठ 53 पर वे कहते हैं -

"क्योंकि वास्तव में भागीदारी (जैसा कि इस मामले से पता चलता है) कभी-कभी विस्तार से अस्पष्ट हो सकती है, यह धारणा न्यायशास्त्र और न्याय द्वारा स्थापित किया जाता है कि वास्तविक उपस्थिति और पूर्व प्रोत्साहन का अर्थ भागीदारी के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। धारा 114 द्वारा उठाई गई धारणा मामले को धारा 34 के दायरे में लाती है।

पृष्ठ 55 पर वह धारा 34 के बारे में कहते हैं कि-"अपराध के वास्तविक कृत्य में भागीदारी और संयुक्त कार्रवाई, सार में, ऐसे मामले हैं जो उकसाने या प्रयासों के विपरीत हैं।" गलत दिशा स्पष्ट है और यह मामले की जड़ तक जाता है क्योंकि जूरी ने भारतीय दंड संहिता की धारा

409 के तहत दोषी का फैसला सुनाया-जिसे केवल धारा 34 के साथ पढ़ा गया और धारा 109 के साथ पठित धारा 409 के तहत नहीं। यह पहले अभियुक्त के बचाव का हिस्सा है कि वह उस समय मौजूद नहीं था जब सामान लादा गया था और न ही वह मौजूद था जब उन्हें फाटकों से बाहर निकलने की अनुमति दी गई थी, अर्थात जब अपराध किया गया था तो वह मौजूद नहीं था। यह सच है कि यह दिखाने के लिए सबूत हैं कि जब लॉरी चली गई तो वह वहाँ था, लेकिन इस तथ्य के अलावा कि इस मुद्दे पर एक छोटी सी विसंगति है, इस बात का संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं है कि इस सबूत पर विश्वास किया गया था।

यदि वह उपस्थित नहीं होता तो उसे उकसाने के लिए दोषी ठहराया जा सकता था यदि जूरी उस प्रभाव के लिए एक निर्णय वापस कर देती क्योंकि सबूत उकसाने और उकसाने के बारे में आरोपः कानून में सही है, लेकिन जूरी ने आरोप के उकसाने वाले हिस्से को नजरअंदाज कर दिया और हमारे पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि क्या वे मानते हैं कि सबूत का यह हिस्सा या भी एक महत्वपूर्ण बिंदु पर गैर-निर्देश है, जो न्याय की विफलता का कारण बन सकता है। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि आरोपी ने मोहसिनभाई को रुपये की राशि में सामान का निपटान किया। 4, 000 जो 10 तारीख को दूसरे अभियुक्त को विधिवत भुगतान किया गया था। विद्वत विचारण न्यायाधीश ने जूरी को बताया कि"रुपये के भुगतान के बारे में अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य।

4,000 पूरी तरह से कम उपयोगी साबित होता है ", और उन्हें यह बताने में कि उन्होंने उन्हें कई कारण क्यों दिए। लेकिन उन्होंने उन्हें यह बताते हुए इसका पालन करना छोड़ दिया कि यदि वे अभियोजन मामले के इस हिस्से को अस्वीकार कर देते हैं, जैसा कि उन्होंने उन्हें करने के लिए आमंत्रित किया था, तो अभियुक्तों के खिलाफ मामले का सबसे मजबूत हिस्सा ध्वस्त हो गया क्योंकि अभियुक्त की स्थिति में अधिकारी इस तरह के अवैध कार्य नहीं करते हैं और खुद को अभियोजन और संभावित अपमान के लिए उजागर करते हैं जब तक कि वे किसी मजबूत उद्देश्य, आमतौर पर स्व-हित से प्रेरित नहीं होते हैं; और हालांकि एक दोषसिद्धि सबूत पर आधारित हो सकती है जो एक मोती वी. ई. का खुलासा नहीं करती है यदि तथ्य इस तरह के पाठ्यक्रम को उचित साबित करते हैं, फिर भी आरोपी की ओर से आपराधिक व्यवहार के लिए पर्याप्त कारण का संकेत देने वाले सबूत के अभाव में वर्तमान जैसे मामले में दोषी ठहराना आमतौर पर असुरक्षित होगा। यदि जूरी को यह बताया जाता, जैसा कि उन्हें होना चाहिए था, तो यह संभव है कि वे दोषी होने का फैसला वापस नहीं करते।

इन परिस्थितियों में, हमारे पास इस दोषसिद्धि को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब हमें इस बात पर विचार करना होगा कि क्या फिर से मुकदमा चलाया जाना चाहिए। चूँकि वर्तमान मुकदमा दूसरे अभियुक्त के खिलाफ आगे नहीं बढ़ सकता है, और जैसा कि कहा जाता है कि सभी अभियुक्तों ने एक सामान्य योजना में एक निर्धारित भूमिका

निभाते हुए सामूहिक रूप से काम किया है, हमें नहीं लगता कि पुनः मुकदमे का निर्देश देना सही होगा, हालांकि यह सामान्य तरीका है. जब एक जूरी परीक्षण को गलत दिशा और गैर-निर्देश के आधार पर अलग कर दिया जाता है। इसलिए हम दोनों अपीलार्थियों को या तो पूरे मामले को छोड़ने या इस तरह से आगे बढ़ने के लिए सरकार पर छोड़ देते हैं (बरी नहीं करते हैं) जिसकी सलाह दी जा सकती है। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अभियुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप को एक अलग मुकदमे के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए, इसलिए दोनों दोषसिद्धि को रद्द कर दिया जाता है और सजा भीः हमें बताया गया है कि पहला आरोपी पहले ही अपनी सजा काट चुका है। जुर्माने का भुगतान करने पर उसे वापस कर दिया जाएगा। दूसरे आरोपी का जमानत मुचलका रद्द कर दिया जाएगा।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।